चौथी औद्योगिक क्रांति यूपी से

सीएम योगी बोले- 96 लाख एमएसएमई इकाइयां औद्योगिक विकास की नींव

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी चौथी औद्योगिक क्रांति का जनक होगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) प्रदेश की ताकत हैं। 96 लाख एसएमएमई इकाइयों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास की नींव रखी है।

लोकभवन सभागार में शुक्रवार शाम आयोजित संतकबीर हथकरघा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते छह साल में सरकार ने एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहित करने के साथ हस्तशिल्पियों, कारीगरों को प्रशिक्षित व सम्मानित किया है। यदि इन्हें पिछली सरकारों ने सम्मान दिया होता तो यूपी बहुत आगे होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 33.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश करार से यूपी अब निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभरकर सामने आया है।

कोरोना काल में देश ने यूपी की एमएसएमई की ताकत को देखा था। तब 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को एमएमएसमई इकाइयों में रोजगार दिया गया। प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए पहली प्राथमिकता है कि कानून का राज हो। दूसरी प्राथमिकता है कि शासन नेक नियती से काम करे, व्यापार की सुगमता हो। लेकिन सबसे आवश्यक है कि एमएसएमई का बेहतरीन क्लस्टर हो। यूपी के एमएसएमई उद्यमियों ने इसे बनाया है। >> आत्मनिर्भर भारत की बैकबोन बना ओडीओपी... पेज 11

39 बुनकर सम्मानित

सीएम ने 39 बुनकरों को नकद राशि, प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। प्रदेश के उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 25 वस्तुओं से जुड़े 75 निर्यातकों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय राज्य निर्यात पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 20 उद्यमियों को एमएसएमई उद्यम राज्य पुरस्कार दिए। 600 कारीगरों को टूलकिट वितरित किए गए।

विद्युत बिल में राहत जल्द

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बुनकरों के लिए विद्युत की फ्लैट दरें जल्द लागू करने जा रही है। बुनकरों की कला को ग्रहण न लगे इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन बुनकरों को स्वयं भी खड़े होने की तैयारी करनी चाहिए।

वाराणसी समेत यूपी के तीन शहर बनेंगे निर्यात के उत्कृष्ट केंद्र

नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों में पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने वर्ष 2030 तक निर्यात को दो लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए प्रोत्साहन की जगह छूट व पात्रता आधारित व्यवस्था को अपनाया जाएगा। इससे भारतीय रुपये को वैश्विक मुद्रा बनाने और ई-कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलेगी। शुक्रवार को घोषित बहुप्रतीक्षित नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी)-2023 में यह लक्ष्य तय किया गया है।

वर्ष 2030 तक दो लाख करोड़ डॉलर के निर्यात का लक्ष्य

नई नीति में हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में वाराणसी, हैंडीक्राफ्ट में मुरादाबाद और कालीन व दरी के क्षेत्र में मिर्जापुर निर्यात के उत्कृष्ट केंद्र बनाए जाएंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि नई नीति शनिवार से लागू हो जाएगी। इससे न सिर्फ चीन को झटका लगेगा बल्कि दुनियाभर में मेक इन इंडिया का डंका बजेगा। विदेश व्यापार महानिदेशक संतोष सारंगी ने कहा कि परंपरागत रूप से पंचवर्षीय विदेश व्यापार नीति की घोषणा की जाती रही है। लेकिन, सरकार बिना किसी अंतिम तिथि के एक गतिशील और उत्तरदायी विदेश व्यापार नीति लेकर आई है।
>> बढ़ेगा ई-कॉमर्स : कारोबार